समता

शासन सम्मेलन [19-20,2017 जनवरी]

संक्षिप्त उद्घाटन सम्बोधन

उपेंद्र बख्शी

[U.Baxi@warwick.ac.uk]

आप सभी के साथ होने का एक दुर्लभ सम्मान है।

यह प्रमाणित है कि भारत पांचवीं अनुसूची की संवैधानिक प्रत्याभूति है और मील का पत्थर माना जाने वाला 'समता निर्णय' के माध्यम से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्यावरण शासन में काफी प्रगति कर रहा है। ये सफलता के मानक बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा मुझे खुशी है कि इस अवसर में आप पांचवीं और छठी अनुसूचियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और लोगों के संघर्ष को हकीकत में बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा है कि (The Crisis of the Indian Legal System, 1982) यदि सकल घरेलू उत्पाद को ध्यान में लिया जाता है तो यह कहा जा सकता है कि भारत अच्छी तरह से विकसित नहीं किन्तु अति विकसित है यदि हम सब सकल विधायी उत्पाद को विचार में ले ।

मेरे पास जो भी कम समय है, मैं संक्षेप में दो पहलुओं पर प्रकाश डालूंगा: (i) एपिस्टेमीसाईड तथा एकोसाईड जो मौद्रिक खनन सक्रियता में लाता है, तथा (ii) ज्ञानमीमांसा को निर्विवाद रूप से मानव अधिकार के अधीन राष्ट्रीय पर्यावरण शासन के अभिन्न अंग के रूप में मंज़ूर करने की जरूरत है।

एकोसाईड[1] का तात्पर्य है - पर्यावरण का प्रचंड विनाश और उसके साथ का दुष्ट औचित्य/ स्पष्टीकरण ।

एपिस्टेमीसाईड[2] का तात्पर्य है - स्वदेशी ज्ञान और स्वदेशी भाव से सोचने तथा वैकल्पिक धारणा स्पष्ट व्यक्त करने की क्षमता का विनाश जो अच्छे जीवन के लिए ज्ञान प्रदान करता है।

खनन की कहानियाँ एक सन्निहित उदाहरण हैं एकोसाईड और एपिस्टेमीसाईड की जो बताता है कि आदमी और पर्यावरण पर यह (खनन) क्या नकारात्मक प्रभाव करता है। यह एक प्रारंभिक सवाल उठता है कि क्यों दुनिया भर में आख्यान के प्राचुर्य मौजूद हैं, लेकिन कारवाई बहुत कम होती क्या हम कह सकते हैं कि यह कथा और निष्क्रियता के बीच का जैविक संबंध हैं?

---

[1] See, Polly Higgins, *Eradicating Ecocide: Laws and Governance to Prevent the Destruction of Our Earth*, (Shepheard-Walwyn, London, 2010, 2015); *Ead.,Earth Is Our Business: Changing The Rules of The Game*, (Shepheard-Walwyn, London (2012).

[2] A category developed mostby Bonaventura de Souza Santos in the context of emancipation: see Santos,*Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide* (London, Routledge, 2014).

जितना अधिक हम अनुसूचित जनजातियों के मूल मानव अधिकारों के हनन की डरावनी कहानियां सुनाएंगे उतना कम सामाजिक कार्रवाई उनके बचाव में होगी। किसी भी गहन अध्ययन के अनुसार दोनों शासक और शासन के वर्ग के चरित्र और विरोध की प्रक्रियाओं का पता चलता है।

पाठ्यक्रम का एक कारण यह है कि हम यह बता सकें की खनन की प्रक्रिया अभिन्न रूप से पूंजीवाद से संबंधित है और आप पूँजीवादी के विकास की कल्पना किए बिना कुछ असाधारण कर नहीं सकते जिससे "कॉर्पोरेट ने अन्दर तालिस्म" की तरक्की हो ।

इस विषय पर बहुत ज़्यादा लिखा जा चुका है ।

उदाहरण के लिए सामाजिक साहित्य में राज्य के विकृत मामलों की रक्षा को "बहुत होने का मिथ्याभास " या 'संसाधन अभिशाप' के रूप में जाना जाता है । अंतर अमेरिकी विकास बैंक (आईडीबी), अपने वार्षिक रिपोर्ट और कई तकनीकी अध्ययन में यह तर्क दिया है कि 'विकास भूगोल से निर्धारित होता है तथा जो देश भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक होते है वह प्राकृतिक संसाधनों में सबसे अमीर होते हुए भी दैवनिर्दिष्ट गरीब होते है और उनका विकाश सबसे धीमी गति से होता है।

यह एक उष्णकटिबंधीय भाग्यवाद है, जिसके अनुसार भूमध्य रेखा के पास के राष्ट्रों को गरीब होना उनकी किस्मत में लिखा हुआ माना जाता है। आईडीबी के एक फैसले के अनुसार जितना अमीर देश प्राकृतिक संसाधनों में होगा उतनी ही धीमी गति से उसकी तरक्की और उतनी ही अधिक आंतरिक असमानताएं[3] होंगी। 'एक ही अभिशाप के दो पहलू' हैं।

हमे यह बारीकी से समझने की आवश्यकता है की कैसे ये राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय संगठन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के लिए नियमों का मेहराब बनाते हैं, की कैसे ये संस्थाएं:

--मानव के सभी अधिकारों का हर तरीके से दमन करना चाहती हैं।

--उचित और उपयुक्त राष्ट्रीय नीतियों और अपने स्वयं के लाभ के लिए कानून बनाना चाहते हैं।

--जिस देश में भोपाल जैसे हादसे हुए वहां भी सीएसआर की बात के माध्यम से प्रतिरक्षा और उनकी गतिविधियों के लिए दण्ड से मुक्ति का एक संस्करण को बढ़ावा देना चाहते हैं।

समष्टिगत अधिनियमों के मंच शिल्प का विकास करने की सोच[4] बनाना चाहते हैं।

--सामाजिक आंदोलनों और संघर्षों को शक्तिहीन करना चाहते हैं।

---

[3] Alberto Acosta, 'Extractivism and Neoextractivism: Two Sides of The Same Curse', https://www.tni.org/files/download/beyonddevelopment_extractivism.pdf

[4] Jen Schneider, Steve Schwarze, Peter K. Bsumek, Jennifer Peeples,'Corporate Ventriloquism', Palgrave Studies in Media and Environmental Communication pp 51-76 (2016).

--राज्य का दबाव और बलप्रयोग (यहां तक कि आतंकी) का प्रयोग संघर्ष के संभावित विनियामक और अन्य परिणामों को नियंत्रित करना चाहते हैं।

--'जमीनी स्तर पर सक्रियता' की प्रथाओं के खिलाफ 'कृत्रिम सक्रियता' को न्यायसंगत बनाने की कोशिश करना।

तो विकल्प क्या हैं।

एक: हमें सतत विकास की नहीं लेकिन 'स्थायी प्रतीपगमन' और उसके बाद के विकास की जरूरत है। यह साक्स की एक चलती टिप्पणी पर आधारित है जहाँ 'पिछले 40 साल को विकास काल कहा जाता है। इस युग का अंत आ रहा है। यह युग अपना मृत्युलेख[5] लिखने के लिए परिपक्व स्थिति है ।

आरटूरो एस्कोबार जानना चाहते है की 'वैश्विक पूंजीवाद और स्थायी समुदायों के निर्माण की प्रतिक्रिया के प्रकोपों का सामना करने के लिए क्या मार्ग अपनाए जा रहे हैं ' और निम्नलिखित तरीके[6] से प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि:

इसके मुख्य घटक पारिस्थितिक न्याय, जैविक और सांस्कृतिक विविधता, जैव क्षेत्रवाद, स्थानीय सत्ता, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र और सहकारी आत्म संगठन हैं । परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा ठोस प्रस्तावों में से एक है - जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं के बगैर समाज कि आत्मनिर्भरता बढ़ाने वाले लक्ष्य के लिए समाज को प्रेरित करना ।

हमें ये समझने की ज़रुरत है कि क्यों 'दुनिया के कई हिस्सों में सांस्कृतिक आलोचकों की बढ़ती संख्या जो विकास की वास्तविक विचार पर प्रश्न उठा रहे हैं । देश भर में महत्वपूर्ण एकजुटता: इक्वाडोर और बोलीविया के सिद्धांतों बेन विविर (अच्छा जीवन /अच्छी तरह से रहना) को मानना[7] । हमें उस अवधारणा को समझने की ज़रुरत है जहाँ हम विकास को पश्चिमी उत्तरी वर्चस्व का एक प्रतिबिंब ना समझें।

मैं जरुरत के हिसाब से एपीस्टेमिक अधिकार पर कुछ टिप्पणियों के साथ निष्कर्ष देता हूँ- निष्कर्ष की ओर बढ़ते हुए, मैं एक ऐसी श्रेणी विकसित कर रहा हूँ जहाँ एपीस्टेमिक मूल मानव अधिकारों का सामना

---

[5] Wolfgang Sachs, *The Developmet Dictionary*, p.1 (London, St. Martin's Press,1992).

[6] See, Escobar, 'Degrowth, Postdevelopment, And Transitions: A Preliminary Conversation',*Sustain Sci* 10:451–462(2015).

[7] Robin Broad & Julia Fischer-Mackey, 'From Extractivism Towards Buen Vivir: Mining Policy As An Indicator Of A New Development Paradigm Prioritising the Environment', Third World Quarterly, (2016); DOI: 10.1080/01436597.2016.1262741

एपीस्टेमिक अन्याय के साथ होता हो -- एक छवि जो इतने नितांत भाव से मिरांडा फ़्रीकर[8] द्वारा विकसित की गई है ।

संक्षेप में, एपीस्टेमिक मूल मानव अधिकार वह अधिकार है जो आपको जानने समझने और असंतोष से लड़ने तथा 'मानक और विद्यमान' अधिकारों की संरचना को बनाए रखने के लिए हैं। इन अधिकारों के साथ राज्य उस नागरिक समाज के ठोस दायित्व भी आतें हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमा के साथ जीने का अधिकार को वाक्यांष किया गया है।

एपीस्टेमिक मूल मानव अधिकार कहीं भी पूर्ण नहीं हैं लेकिन इनमें एक निर्धारित मानक उपस्थिति है । इन अधिकारों को यथोचित प्रतिबंधित किया जा सकता है लेकिन दबाया नहीं जा सकता है यह दावा करते हुए कि लोग और राज्य कानून के शासन के अधीन रहते है ।

सभी जानकारी और ज्ञान राज्य द्वारा स्वामित्व और यह आधिपत्य जताना कि लोग कैसे भाग लेंगे, ज्यादातर मामलों में उनकी मूल एपीस्टेमिक मानव अधिकारों की अवहेलना और उल्लंघन होगा करना होगा ।

मैं इन अधिकारों पर मेरी सोच कहीं और विकसित करना चाहूंगा। अंत में इतना ही कहना है कि: संप्रभुता से न्याय प्राप्त करना और अतिरिक्त सक्रियता का लक्ष्य खनन के उस आर्थिक आदर्श पर निर्भर है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को बड़े पैमाने पर हटाया जाता है हालांकि इससे मानव अधिकारों का खंडन होता है । हम कैसे गैर-हिंसक भाव से 'विरोधाभास[9]' का आयोजन करें, यह सब लोगों की प्रमुख चिंता का विषय है ।

---

[8] *Epistemic Injustice: Power and the Ethics of Knowing*, (Oxford University Press, 2007).

[9] Cf.Ana Cecilia Dinerstein, 'Organising Negation: NeoliberalHopelessness, Insurgent Hope(Mexico)',link.springer.com/content/pdf/10.1057/9781137316011_4.pdf